

160
2018

नम्बर व तारीख
अद्वैत जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

अपिलान्ट अधिवक्ता उपस्थित ।

कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई । पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे । चूँकि पत्रावली में प्रार्थना पत्र केवियट पेश हुआ है अतः केवियटकर्ता को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 21-02-18 को पेश हो ।

21/2/18
1701
16/2/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। कृषि. कपीलोट एक्ट डेवियट-
कर्ता उपस्थित। डेवियटकर्ता द्वारा जामिन पत्र
स्थगन, एक्ट जामिन पत्र द्वारा 5 पर जजक करके
हेतु रूप चाहा गया। पत्रावली बारते जजक/पहु
जामिन पत्र स्थगन दिनांक 22.02.18 को पेश हो।

appled copy received
V. Duf Ad.
21-2-18
12:30 PM.

22-2-18 पत्रावली प्रस्तुत हुई । कृषि. कपीलोट एक्ट
डेवियटकर्ता। रेस्यो. उपस्थित। समयपहा को
जामिन पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली
बारते कादेश दिनांक 23.02.18 को पेश हो।

पत्रावली बारते कादेश प्रस्तुत हुई। समयपहा
को कादेश नहीं दिखाया जा सका है। पत्रावली
बारते कादेश दिनांक 27.02.18 को पेश हो।

ज्ञान ग्रह पत्रावली बारते कादेश प्राचीन पत्र
स्थगन प्रस्तुत हुई। अतिमाधक प्राची। कपीलार्थी
ने वदस में निवेदन किया कि उनके द्वारा
ख.न 51 दाल ख.न 73 से 76 निमका
रकबा 0.40 हेक्टर है एवं ख.न. 11. निमके
नये नम्बर 23 रकबा 0.29 हेक्टर है, का
हुस वारी। वेसोडेन्ट से किया है एवं उक्त
कादेशी को जजपुर विकास प्राधिकरण को

Examined
& found

रूपान्तरित करवा ली गई है। अब उम्मेद
 दोनो खसरा नम्बरान् की भूमि के सम्बन्ध
 में कृपावीर/वेस्पोडेन्स का कोई संशोधन नहीं
 होने पर भी कृषिगत न्यायालय से इन
 खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में कृषिगत
 निषेधाज्ञा प्राप्त कर पायी। कृषिगत को
 पाबन्द करवा दिया गया है, जिससे
 पायी। कृषिगत को अपूर्णनीय स्तरी
 कारित हो रही है। अतः कृषिगत
 न्यायालय द्वारा पारित कृषिगत की
 विधानात्मक स्थागित करवाई जावे।

कृषिगत कृपावीर/वेस्पोडेन्स
 ने खसरा में निवेदन किया कि
 कृषिगत ख. न. ॥ जिसका रकबा १ बीघा
 १० बिस्वा था, के परिवर्तित नम्बर में
 रकबा ०.३८ हैक्टर होना चाहिये था,
 के स्थान पर मात्र ०.२९ हैक्टर
 बनाये गये। जिससे उसका रकबा ०.०९
 हैक्टर कम किया गया। इसी प्रकार
 खसरा नम्बर ५१ जिसका रकबा २ बीघा
 ६ बिस्वा था का कुल रकबा ०.५८ हैक्टर
 बनता था किन्तु परिवर्तित खसरा
 नम्बर ७३ से ७६ का रकबा ०.५० हैक्टर
 कर दिया गया। जिससे १८ हेक्टर भूमि
 कम हो गई है, जिससे कृषिगत
 न्यायालय द्वारा वादी/पायी के हक
 में कृषिगत निषेधाज्ञा सही तौर पर
 जारी की गई है। अतः पार्वीना पत्र



सहायक अंपाल प्रधिकारी
 जयपुर

एवं कृषील श्वारित करारि जावे।

हमने बहस कागजात पत्राचार पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वर्तमान ख.न 23 एवं 73 से 76 में जो खेती शामिल था का बेचान कृषी/रेसोर्सेट द्वारा जारी। कृषीलोनर को किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम न्यायालय द्वारा उनको परिश्रम करणारि निषेधाया पाबन्ड किया जाना इस स्तर पर उचित प्रतीत नहीं होने से अधिनियम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/11/2017 निरस्त किया जाता है। चूंकि अधिनियम न्यायालय द्वारा उक्त आदेश एकपक्षीय किया गया था। अतः अधिनियम न्यायालय के समक्ष पार्षना पत्र करणारि निषेधाया विचारधीन है अतः कृषील कृषीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर उक्त कृषील अधिनियम न्यायालय को इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पार्षना पत्र करणारि निषेधाया पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर उसका विधिवत निस्तारण करे। दोनों पक्षों को पाबन्ड किया जाता है कि वे अधिनियम न्यायालय से निगत आगामी पेशी दिनांक 16/3/18 को उपस्थित होकर अपना पत्र प्रस्तुत करे।

पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तथ्यीय दाखिल करणारि हो। आदेश सुनाया गया।



जयपुर

034
4